सम्पर्क : नित्या कौशिक, डब्ल्यूआरआई इंडिया : **9819902763,** nitya.kaushik@wri.org

प्रेस विज्ञप्ति

भारत की भूमि को जलवायु और समुदायों के लिये पुनर्स्थापित/बहाल करने का सही अवसर

मध्य प्रदेश के सीधी जिले की 75% जमीन की बहाली से जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ-साथ हजारों नौकरियां तथा छोटे उद्योग भी उत्पन्न हो सकते हैं। स्थानीय लोगों को तेजी से अधिक भूमि बहाली में मदद करने के लिये डब्ल्यूआरआई इंडिया और मध्य प्रदेश सरकार ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं।

नयी दिल्ली/भोपाल, **9 दिसम्बर**, **2020** :भारत के करीब 70 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए खेती और वनों पर निर्भर हैं। इन लोगों की आजीविका खतरे में है। जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि आय में सालाना 25% की गिरावट हो सकती है, जिसके कारण 50% से ज्यादा श्रम शक्ति जोखिम के साये में है। मगर यह अपरिवर्तनीय क्षति नहीं है। अगर जंगलों का संरक्षण और जमीन की बहाली की जाए तो भारत का लगभग आधा हिस्सा यानी करीब 14 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हो सकता है।

डब्ल्यूआरआई इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट 'रीस्टोरिंग लैंडस्केप्स इन इंडिया फॉर क्लाइमेट एंड कम्युनिटीज' (जलवायु तथा समुदायों के लिए भूदृश्यों की बहाली) में मध्य प्रदेश की जलवायु के लिहाज से जोखिम वाले गरीब जिले सीधी में इस अवसर का आकलन किया गया है। शोधकर्ताओं ने पुनरुद्धार से प्राप्त होने वाले पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक लाभों का आकलन करने वाली रीस्टोरेशन अपॉर्चुनिटी असेसमेंट मेथोडोलॉजी (आरओएएम) को अपनाकर पारिस्थितिकीय सेवाओं तथा पुनरुद्धार से जुड़े आजीविका संबंधी लाभ का विश्लेषण किया। इस दौरान उन्होंने भू-धृति (land tenure), लिंग तथा सामाजिक समावेशन को भी ध्यान में रखा।

इस अध्ययन में निम्नांकित तथ्य सामने आए-

- सीधी जिले की 75% जमीन की बहाली से स्थानीय लोगों के लिए 37 लाख 50 हजार चुकता कार्य दिवस पैदा हो सकते हैं। साथ ही मजदूरी तथा पौधों की बिक्री से 1.3 अरब रुपए (1.9 करोड़ डॉलर) की अतिरिक्त आय भी हो सकती है।

WRI INDIA

- अगले 20 वर्षों के अंदर जंगलों में 70 लाख टन कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता है। इससे जैव विविधता का संरक्षण होने के साथ-साथ भूमि कटान पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा।
- बांस, कटहल, आंवला तथा मोरिंगा जैसी कीमती फसलों को बेचने वाले तीन हजार अति लघु उद्योगों की स्थापना होने से रोजगार के 30,000 अवसर पैदा हो सकते हैं।
- स्वस्थ भू-दृश्य उन पर निर्भर समुदायों के लिए भोजन, ईंधन की लकड़ी, चारा तथा गैर-काष्ठ वन्य उत्पाद उपलब्ध करा कर महत्वपूर्ण स्थानीय मांगों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही मिट्टी के कटान का नियंत्रण तथा जैव विविधता का संरक्षण भी कर सकते हैं।

रिपोर्ट में जिले के सामाजिक परिदृश्य का भी विश्लेषण किया गया है: प्रमुख लोग और संगठन जो सूचना और धन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, अधिकार रखते हैं, और प्रेरणा और मध्यस्थता संघर्ष करते हैं। अभिनेता-नेटवर्क संबंधों को समझने से, शोधकर्ताओं ने पाया कि सिविल सोसाइटी संगठनों, स्थानीय अनुसंधान विश्वविद्यालयों को राज्य कर्ताके साथ जिले में बहाली के एजेंडे को चलाने के लिए सबसे आगे रहने की आवश्यकता है।इस रिपोर्ट में उभरे तथ्य यह संकेत देते हैं कि महिलाएं और भारत के सीमांत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग बहाली प्रक्रिया को लागू करते हैं, जो बहाली प्रक्रिया केशायद ही कभी मुख्य नीति निर्धारक बनते हैं। ऐसे में इस प्रकार के तंत्र का विकास किया जाना चाहिए जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। इन वर्गों के लोगों के विचारों तथा पुनर्बहाली की प्राथमिकताओं को एक मंच पर लाना सच्चे आर्थिक तथा पर्यावरणीय अवसर हासिल करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा।

अधिक जमीन का तेजी से पुनरुद्धार करने के लिए एक साझेदारी

सीधी जिले के भूदृश्यों की पुनर्बहाली की संपूर्ण संभावना का पूरा इस्तेमाल करने के उद्देश्य से एक साझा योजना तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और डब्ल्यूआरआई इंडिया ने एक समझौते (एमओयू) पर 9 नवम्बर को हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत जिला पंचायत और ग्रामीण विकास (डीपी एवं आरडी) विभाग तथा डब्ल्यूआरआई इंडिया ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा रोजी-रोटी से जुड़े अन्य कार्यक्रमों, मूलभूत ढांचा विकास, आदिवासी कल्याण तथा पंचायत क्षेत्रों का लाभ उठाने का लक्ष्य तय किया है। इससे भारत सरकार को पेरिस जलवायु समझौते के प्रति अपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (एनडीसी) और बॉन चैलेंज समेत अपनी अंतरराष्ट्रीय संकल्पबद्धताओं की पूर्ति करने तथा 26 बिलियन हेक्टेयर जमीन की पुनर्बहाली के लिए निर्धारित लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रेलिटी लक्ष्य तथा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

WRI INDIA

डब्ल्यूआरआई इंडिया और डीपी एवं आरडी इस बात पर सहमत हुए हैं कि बहाली का काम 1) विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हो, ताकि यह पता चल सके कि पुनरुद्धार से क्या हासिल किया जा सकता है, 2) जैव विविधता मिट्टी तथा पानी जैसी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय सेवाओं को बहाल करके जमीन की उत्पादकता में सुधार तथा भू उपयोग संबंधी चुनौतियों का समाधान करे, 3) लोगों, खासकर महिलाओं के पुनरुद्धार संबंधी परियोजनाओं की योजना तैयार की जाए तथा उन्हें उसके क्रियान्वयन के केंद्र बिंदु में रखा जाए।

आगामी संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी पुनर्बहाली दशक यानी यूएन डिकेड ऑन इको सिस्टम रीस्टोरेशन (2021-30) के दौरान पूरी दुनिया में स्थानीय नीति निर्धारक लोग यह सबक सीख कर जमीन के प्रबंधन की समावेशी प्रणालियां विकसित कर सकते हैं, जिनसे आर्थिक अवसरों को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाया जा सकता है और सर्वाधिक सीमांत लोगों के लिए मूल्य सृजन किया जा सकता है।

उद्धरण-

श्री मनोज श्रीवास्तव- अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश

हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और वाटर शेड कार्य को एक साथ लाने के लिए एक समग्र, व्यापक और संयुक्त दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं। सीधी जिले ने अपघटन का सामना किया है और उसने पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी सेवाओं को खो दिया है। भूदृश्य के पुनरुद्धार में सीधी जिले में एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करने की क्षमता है जो अव्यवस्थित हो चुके प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्नवीनीकरण, पुनर्प्रारूपण और प्राकृतिक संसाधनों को फिर से संगठित करने पर आधारित हो। इस सहयोगात्मक प्रक्रिया में लोगों का सहयोग केंद्रीय भूमिका में होगा। हमारे पास राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद होगी और लिंग विशिष्ट तरीके से बदलाव आएगा। बहाली के मामले में महिलाएं सबसे आगे होंगी ।स्वयं सहायता समूहों, क्लस्टर स्तरीय संघों तथा ग्राम संगठनों की मदद से अनेक कदम उठाए जाएंगे।

डॉक्टर ओ पी अग्रवाल- सीईओ, डब्ल्यूआरआई इंडिया

डब्ल्यूआरआई इंडिया के लिए परियोजनाओं को तैयार करने के पीछे की प्रेरणा यह देखने की होती है कि जमीन पर उनका क्रियान्वयन हो और बदलाव नजर आए। यही वजह है कि हम सीधी जिले में समृद्धि और ग्रामीण रोजगार को बहाल करने के मिशन में मध्य प्रदेश सरकार के साथ काम करके बेहद प्रसन्न

हैं। अब इस दृष्टिकोण को पूरे भारत और पूरी दुनिया में लागू करने का वक्त है। खास तौर पर यू एन डिकेड आन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन (2021-2030) के दौरान।

श्री आर. परशुराम- पूर्व मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, एवं वर्तमान सीनियर फेलो- डब्ल्यूआरआई इंडिया

"डब्ल्यूआरआई इंडिया वैश्विक स्तर पर लैंडस्केप के पुनरुद्धार की रूपरेखा तैयार करने और उसे जमीन पर उतारने के कार्य में सक्रिय भागीदार रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा डब्ल्यूआरआई इंडिया के बीच भूदृश्य बहाली को अमलीजामा पहनाने के लिए किया गया एमओयू प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिहाज से गेम चेंजर साबित हो सकता है। सीधी जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों के दूसरे स्थानों पर विस्थापन के इतिहास को देखते हुए यह एमओयू इस जिले में ग्रामीण आजीविका के अवसरों का विस्तार करने में मदद करेगा। साथ ही साथ भू अपघटन की समस्या के समाधान और वर्षा पर निर्भर कृषि के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा।"

डब्ल्यू आर आई इंडिया की सस्टेनेबल लैंडस्केप एंड रीस्टोरेशन शाखा की निदेशक **डॉक्टर रुचिका सिंह** और इसी इकाई की प्रबंधक **मैरी दुरईसामी**-

"सीधी जिले को देखकर मिले सबक हमें लैंडस्केप के स्तर को लेकर और अधिक सुगठित योजना पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। यह रास्ते बड़े पैमाने पर प्रकृति आधारित समाधानों की संभावनाओं के द्वार खोलते हैं, जिनमें उनसे संबंधित परियोजनाओं में लोगों की केंद्रीय भूमिका हो। भारत में भूदृश्य बहाली की असीम संभावनाएं हैं और 10 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा ऐसे क्षेत्र हैं, जहां जलवायु संरक्षण के लिए विभिन्न उपयोगों के तहत पेड़ उगाए जा सकते हैं। एक संवादात्मक और वेब आधारित मंच के जरिए इसका आकलन किया गया है, जिससे वरीयता वाले क्षेत्रों का पता मिलता है। जैसा कि अध्ययन में पाया गया है कि भूदृश्य पुनर्बहाली के अनेक लाभ हैं। इस क्षमता को अनलॉक करने के लिये तंत्र को डिजाइन करना होगा ताकि लाभ लोगों, विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले पुरुषों और महिलाओं को मिल सके।

***

डब्ल्यूआरआई इंडिया के बारे में: *डब्ल्यूआरआई इंडिया विशेषज्ञों की सहभागिता वाला एक शोध संगठन है जो आर्थिक अवसर और मानव कल्याण की बुनियाद यानी स्वस्थ पर्यावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से बड़े विचारों को जमीन पर उतारने के लिए नेतृत्वकर्ताओं के साथ करीबी सहयोग से काम करता है। हमारी सोच एक ऐसी समानतापूर्ण और समृद्ध धरती का निर्माण करना है, जिसका संचालन प्राकृतिक संसाधनों के बुद्धिमता पूर्ण प्रबंधन के जरिए हो। हमारी आकांक्षा एक ऐसी दुनिया बनाने की है जहां सरकार उद्योग जगत तथा समुदायों द्वारा किए जाने वाले कार्य एक साथ मिलकर गरीबी को हटाने और सभी के लिए कुदरती पर्यावरण बनाए रखने के उद्देश्य से हों।*